गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान कलेक्टर-कमिश्नर को निर्देश देते मुख्य सचिव आर.परशुराम।

एक जुलाई तक दिलाएं दाखिला

नगर संवाददाता, भोपाल

स्कूल चले अभियान में स्कूल में दाखिल करवाने में शेष बच्चों का हर हाल में एक जुलाई तक स्कूल में दाखिला करवाया जाए। इसके साथ ही निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को पदस्थ किया जाए। यह निर्देश मुख्य सचिव आर परशुराम ने गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग परख में सभी कलेक्टर और कमिश्नर्स को दिए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में नागरिकों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की और संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की।

◆ परख में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने बारिश का मौसम शुरू होने पर रोगों के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाएं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि बाढ़ के उद्यव के लिए संबंधित अमले को सक्रिय रखें। मुख्य सचिव ने अनुकंपा नियुक्ति के दो जिलों में शेष प्रकरणों की कार्यवाही पूर्ण करने को भी कहा।

परख में नहीं हुई गेहूं भंडारण पर चर्चा: मुख्य सचिव श्री परशुराम ने परख में कलेक्टर और कमिश्नर से कई बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन उचित भंडारण के अभाव में बारिश में सड़ने वाले गेहूं को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इतना ही नहीं परख में मौजूद खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने भी कलेक्टरों को गेहूं के उचित भंडारण को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए। उल्लेखनीय है कि प्री मानसून की बारिश में ही खरीद केन्द्रों में खुले में पड़ा गेहूं पानी में भीगने के कारण सड़ रहा है। अकेले दतिया जिले की कृषि उपज मंडी और खरीद केन्द्रों में सोमवार को प्री-मानसून में हजारों टन गेहूं पानी में भीग गया।

टेली समाधान नागरिक सहायता केंद्र

परख में हरि रंजन राव सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने बताया कि प्रदेश में सितंबर 2008 से अब तक टेली समाधान योजना में 27 लाख फोन काल आए हैं। इस अवसर पर नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी एवं शिकायतें दर्ज करवाने के लिए संचालित काल सेंटर नागरिक सहायता केंद्र की जानकारी विस्तार से दी गई। टोल फ्री नंबर 155343 एवं 1800-2335343 पर प्रदेश के सभी जिलों से लैण्ड लाइन और मोबाइल से बिना कोड डायल किए काल किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि टेली समाधान काल सेंटर योजना के माध्यम से और अधिक जनसमस्याएं सुलझाने पर ध्यान दिया जाए। परियोजना के लिए जिला एवं विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए।